

प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून:

दिनांक: 09 अप्रैल, 2013

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-12, 30 एवं 31 के अन्तर्गत वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.03.2013 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के लिये स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष अनुदान सं०-12 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में ₹14165.15 लाख एवं आयोजनेत्तर मदों में ₹47104.41 लाख, अनुदान सं०-30 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में ₹1039.30 लाख तथा अनुदान सं०-31 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में ₹484.10 लाख इस प्रकार कुल ₹62792.96 लाख (छ: अरब सत्ताईस करोड़ बयानबे लाख छियानबे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न हार्ड कॉपी के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपके निर्वर्तन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग-1 के शासनादेश संख्या- 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं०-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.03.2013 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2014 तक कर लिया जाय, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7. भारत सरकार को समय से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, जिसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-12, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नकों में वर्णित लेखाशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.03.2013 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : ऑन लाईन एलाटमेन्ट की प्रति

भवदीय,
/ (अतर सिंह)
उप सचिव

सं०-602(1)/XXVIII-5-2013-23/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरोय बिल्डिंग भाजरा, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-3/नियोजन विभाग/एन०आई०सी०।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
/ (अतर सिंह)
उप सचिव